अनिश्चित समयः भारत के तेल आयात पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

26 अप्रैल, 2019

"भारत को अपने तेल आपूर्तिकर्त्ता आधार में विविधता लाने और ऊर्जा के घरेलू स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है।"

आपूर्ति पर अनिश्चितता के एक बड़े सौदे के साथ तेल बाजार एक बार फिर से खस्ताहाल है। सोमवार को अमेरिका ने घोषणा की कि वह ईरान से तेल खरीदने के लिए भारत सहित आठ देशों को दी गई 180 दिन की छूट को 1 मई से आगे नहीं बढ़ाएगा। इसके कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत पिछले हफ्ते के 71.97 डॉलर से 75 डॉलर से अधिक अचानक बढ़ गई, क्योंकि व्यापारियों ने बाजार में

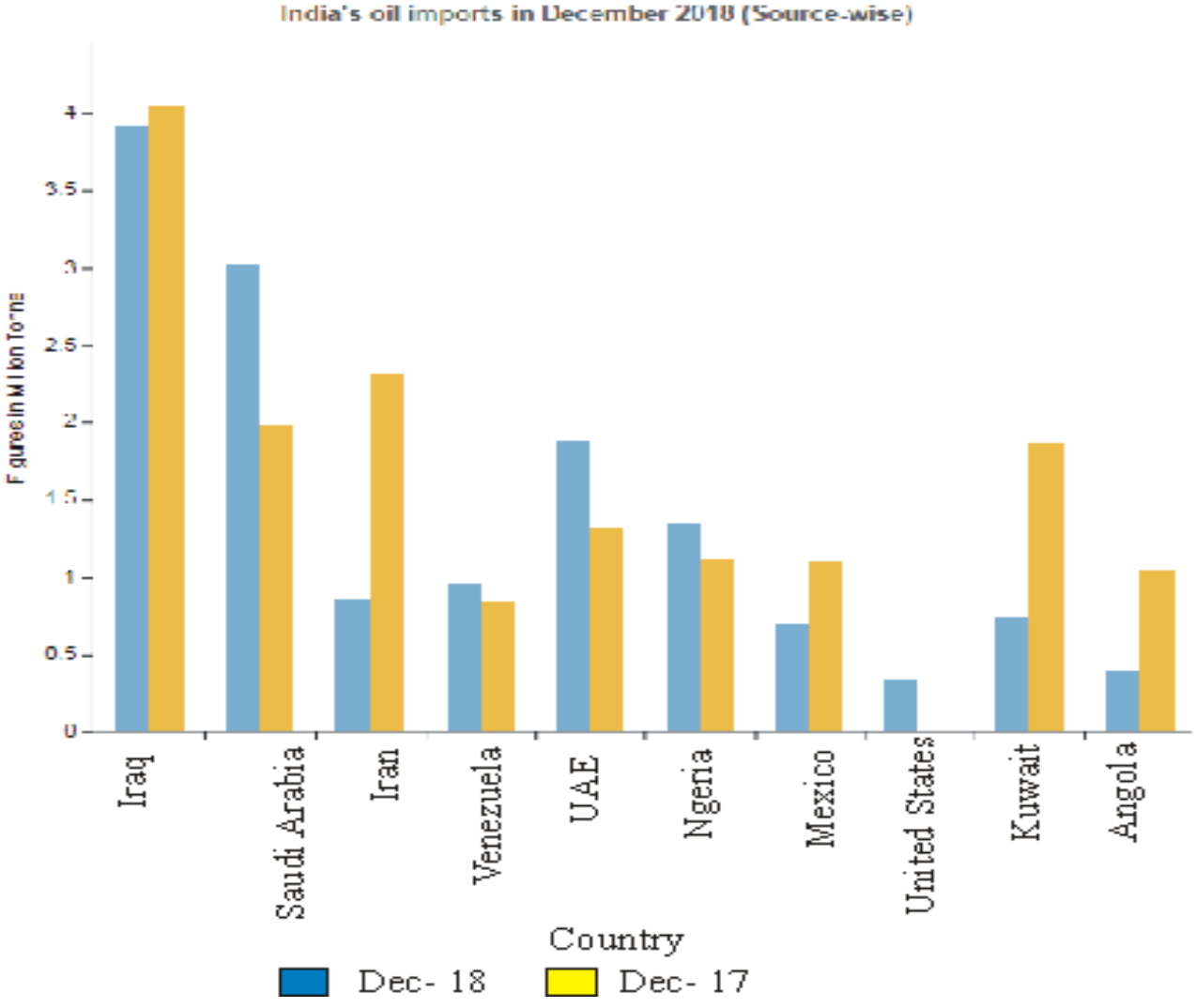

प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही तेल की आपूर्ति में छूट मिलने की उम्मीद की थी।

यह ध्यान देने योग्य है, कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत पिछले कुछ महीनों में लगातार बढ़ रही है और लगभग 50% की वृद्धि इसमें हुई है, जो कि दिसंबर में लगभग 50 डॉलर के निचले स्तर पर पहुंच गयी थी। ऐसा संगठन के निर्णय के परिणामस्वरूप हुआ है जहाँ पेट्रोलियम निर्यातक देश (ओपेक) कीमतों को बढ़ावा देने के लिए अपने उत्पादन को रोकते हैं।

भारत अपने कच्चे तेल का 10% से अधिक ईरान से आयात करता है। इसलिए सरकार को अपनी विशाल ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं को खोजने की तत्काल चुनौती का सामना करना पड़ता है। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि उच्च अर्थव्यवस्था की कीमतों में नकारात्मक प्रभाव भारत के चालू खाते घाटे, राजकोषीय घाटे और व्यापक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पर पड़ेगा।

तेल की कम कीमतों की बदौलत चालू खाता घाटा, जो दिसंबर तिमाही में जीडीपी का 2.5% तक सीमित था, आगे चलकर और अधिक खराब होगा। राजकोषीय घाटा, जो चुनावों से पहले व्यापक हो चुका है, के भी नियंत्रण से बाहर होने की संभावना है। हालांकि, मुद्रास्फीति इस समय अपेक्षाकृत सौम्य है, लेकिन मूल्य लाभ में किसी भी तरह की तेजी भारतीय रिजर्व बैंक के हाथ बांध देगी।
हालांकि, यह कहना मुश्किल है कि इस सप्ताह तेल की कीमत में उछाल और पिछले कुछ महीनों में कमोडिटी की कीमत में वृद्धि का संकेत है। तेल बाजार में अमेरिकी शेल उत्पादकों के प्रवेश ने तेल की कीमत पर रोक लगा दी है क्योंकि स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा करने वाले शेल आपूर्तिकर्ता अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए खुश होत हैं जब भी तेल की कीमतें काफी बढ़ जाती हैं।

इस हफ्ते भी, ईरान से तेल आयात करने के लिए दी गई छूटों के अंत की खबरों और यू.एस. से बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ने की खबरों के बीच तेल बाजार में उछाल आया है। अगर भारत को वैश्विक अस्थिर तेल बाजार में अपने हितों की रक्षा करनी है, तो सरकार को अपने आपूर्तिकर्त्ता आधार में विविधता लाने और ऊर्जा आपूर्ति के घरेलू स्रोतों को बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाने की आवश्यकता होगी।

अधिक निवेश के लिए अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ाने से देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वैश्विक बाजार से तेल पर निर्भरता से बचने में मद्द मिलेगी।

GS World टीम...

तेल की बढ़ती कीमतें

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में अमेरिका ने ईरान से तेल आयात संबंधी प्रतिबंधों में छूट, सिग्निफिकेंट रिडक्शन एक्सीप्शंस (Significant Reduction Eñceptions- SREs) को रोकने का फैसला किया है। जिसके कारण कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने की संभावना काफी बढ़ गयी है।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिका ने पिछले वर्ष नवंबर में भारत और सात अन्य देशों को 180 दिनों की अवधि के लिये ईरान से तेल आयात में छूट दी थी, जो 2 मई को समाप्त होने वाली है।
- भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और तुर्की इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।
- इटली, ग्रीस और ताइवान (वर्तमान में छूट पाने वाले देश) ऐसे तीन देश हैं, जिन्होंने पहले ही अपने आयात को शून्य कर दिया है।

प्रतिबंध का प्रभाव

- ईरान के राजस्व का मुख्य स्रोत तेल निर्यात है जो प्रतिबंध की वजह से संकट में आ जाएगा।
- वर्ष 2018 में वैश्विक तेल उत्पादन में ईरान का हिस्सा 4% था। ईरान पर प्रतिबंधों के पश्चात् वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखलाओं पर असर पड़ने की संभावना है।
- आपूर्ति में व्यवधान की वजह से तेल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
- दुनिया के तीन सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादकों अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि वे वैश्विक तेल बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
- अमेरिका ने कहा है कि वह तेल प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली किसी भी संस्था या कंपनी पर वित्तीय अंकुश लगाएगा, जिसमें कंपनियों द्वारा स्विफ्ट बैंकिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सिस्टम के उपयोग पर प्रतिबंध, उन कंपनियों की किसी भी अमेरिकी संपत्ति की जब्ती और डॉलर में लेन-देन जैसे प्रतिबंध शामिल हैं।

भारत पर प्रभाव

- रिफाइनरियों के लिये तेल की आपूर्ति: अमेरिका के इस निर्णय से भारत पर काफी प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- अमेरिका ने हाल ही में भारत के एक अन्य शीर्ष आपूर्तिकर्त्ता वेनेजुएला पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। इन परिस्थितियों में

अमेरिका का हालिया निर्णय भारत के लिये मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

- आयात बिल में वृद्धि से रुपए पर दबाव पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से महँगाई बढ़ेगी।

ईरान द्वारा प्रदत्त भारत को विशेषाधिकार

- ईरान अन्य देशों को 30 दिन और भारत को 60 दिन की क्रेडिट सीमा देता है।
- ईरान ने भारत को सीधे रुपए में भुगतान करने की भी सुविधा प्रदान की थी। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि कुल राशि का 55% भुगतान यूरोपीय बैंकों में किया जाएगा तथा शेष 45% राशि का भुगतान भारत स्थित बैंक में किया जाएगा जिसका उपयोग भारत से आयात के लिये किया जाएगा।
- इसके बाद, यूरोपीय बैंकों द्वारा भुगतान बंद किये जाने की स्थिति में ईरान ने भारत को 100% भुगतान रुपए में करने की सुविधा दी, यह व्यवस्था ईरान के साथ P 5+1 देशों की संधि होने तक जारी रही।
- पुन: 55% भुगतान यूरो और 45% रुपए में करने की व्यवस्था की गई।
- ईरान भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति के लिये माल ढुलाई में भी छूट प्रदान करता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. ओपेक एक स्थायी, अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना सितम्बर, 1960 में आयोजित बगदाद सम्मेलन के दौरान हुई थी।
2. संयुक्त अरब अमीरात ओपेक के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
3. हाल ही में कतर ने ओपेक से अपनी सदस्यता को स्थगित कर दिया है।
4. ओपेक का मुख्यालय दुबई में स्थित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 1 और 3
(c) 1, 3 और 4
(d) उपर्युक्त सभी

1. Consider the following statements-

1. OPEC is a permanent, inter-governmental organization, which was established during the Baghdad conference organized in September 1960.
2. United Arab Emirates is one of OPEC's founding members.
3. Recently, Qatar has postponed its membership from OPEC.
4. OPEC headquarter is located in Dubai.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) 1 and 3
(c) 1, 3 and 4
(d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:- वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। भारत जैसे विकासशील देश को इस गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए नए वैकल्पिक ऊर्जा के स्त्रोतों को हर हाल में तलाशना होगा। भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में अभी तक उठाये गए कदमों की चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

Q. In present global scenerio, the increasing Crude Oil price is negetively affecting Indian economy. India must have to search for an alternative energy source for the solution of this severe problem. Discuss the steps taken by the goverment in this direction till now. (250 Words)

नोट : 25 अप्रैल को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2 (c) होगा।